

E Learning Study Material
By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR
BA PART THIRD ECONOMICS HONS
PAPER SIX

Effects of HIGH TARIFFS

उच्च शुल्क काल का प्रभाव

सन् 1861 के मॉरिल शुल्क (MORILL TARIFF) ने उच्च शुल्क प्रणाली का उद्घाटन किया। पहले सन् 1833 से 1861 तक प्रचलित शुल्क न्यूनीकरण नीति को पूर्णतः उल्ट दिया। गृह युद्ध काल में न केवल मॉरिल शुल्क को बनाये रखा गया। अपितु उल काल में कांग्रेस का ऐला कोई भी सन् नहीं हुआ जिसमें शुल्क दर में वृद्धि नहीं की गयी हो। 1864 का शुल्क अधिनियम सभे बहुत महत्वपूर्ण था जिसने सामं वस्तुओं पर शुल्क की दरों को बढ़ा दिया। शुल्क की औसत दर को बढ़ा कर 47 प्रतिशत कर दिया गया। गृह-युद्ध को संशानित करने के लिए मुद्रा की व्यवस्था की जानी आवश्यक था सामरिक उद्योग संरक्षण की मांग का रहे थीं, औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादक ऊँची शुल्क दर के लिए खेद शोर मचा रहे थे ताकि वे अनारोपित किए

जा रहे आन्तरिक उत्पादन शुल्कों की विस्तृत प्रणाली के प्रभाव को दूर कर सके। गृह-युद्ध के बाद दक्षिणी राजप पुनः कांग्रेस में लौटने में अवश्य आए थे किन्तु जब उनकी शक्तियों में महान् क्षात हो गया था। फलतः उच्च संरक्षण प्रशुल्क का प्रचलन एवं प्रभाव क्रियाशील रहा।

लेकिन ये गृह युद्धकालीन प्रशुल्क अर्थशास्त्रिक अर्थशास्त्रिक एवं अनावश्यक रूप से अधिक उंची थीं। अतः स्वभावतः गृह युद्धोत्तर वर्षों में प्रशुल्क सुधारकों द्वारा उनकी कड़ी आलोचनाएं की गयीं। 1870 के प्रशुल्क अधिनियम ने कुछ वस्तुओं के प्रशुल्क को कम करने का प्रयास किया। फिर 1872 ई० में प्रायः सभी वर्ग की वस्तुओं के प्रशुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की गयी। प्राय, काँची आदि पर करों (taxes) को विलकुल समाप्त कर दिया गया। किन्तु यह कमी काफी कम समय तक ही लागू रही। 1873 ई० में फिर आर्थिक संकट शुरू हो गया जिससे 1872 ई० में प्रशुल्क दरों में पुनः वृद्धि की गयी तथा 1874 ई० के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1881 ई० तक सरकारी आय में प्रयाप्त सुधार हो गया। अतः प्रशुल्क के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 1883 ई० में प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) की स्थापना की गयी। स्थापना का वर्ष 1883 था।